RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : बुधवार 28 फरवरी 2024 वर्ष 05 अंक 307 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

महाराष्ट्र बजट 2024:

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट की मुख्य विशेषताएं

बुनियादी ढांचे पर जोर...

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया। वित्त मंत्री अजीत पवार ने वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के कुल व्यय के लिए 6 लाख 522 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया। बजट में 4 लाख 98 हजार 758 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह और 5 लाख 8 हजार 492 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय दिखाया गया है। राजस्व घाटा 9,734 करोड़ रुपये और राजकोषीय घाटा 99,288 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। अंतरिम बजट में चार माह का बजट आवंटन अनुमोदन हेतु रखा गया है। शेष बजट लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा।

बजट में समाज के सभी वर्गों को न्याय और विकास के अवसर

वित्त मंत्री ने कहा कि हालांकि यह राज्य का अंतरिम बजट है, इसके बावजूद बजट में किसानों, मजदूरों, महिलाओं, छात्रों, युवाओं, पिछड़े वर्गों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, उद्यमियों, व्यापारियों और पेशेवरों जैसे समाज के सभी वर्गों को न्याय और विकास के अवसर प्रदान करने का प्रयास किया है। अंतरिम बजट में भी राज्य की सतत, पर्यावरण अनुकूल, समावेशी विकास की नीति को गति देने को प्राथमिकता दी है।

निर्यात बढ़ाने के लिए पांच औद्योगिक पार्क

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम में 450 करोड़ और निर्यात योग्य घटकों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बजट में रखा गया। वित्त मंत्री ने कहा कि पांच औद्योगिक पार्कों के निर्माण के माध्यम से निर्यात बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। मेक इन इंडिया पहल के तहत नवी मुंबई में एक मॉल स्थापित करने के लक्ष्य के साथ 196 करोड़ रुपये की निविदा प्रक्रिया शुरू की है।

जनवरी 2024 में दावोस में 19 कंपनियों के साथ उल्लेखनीय समझौते किये गये। कपड़ा नीति के तहत राशन वितरण और प्रति महिला एक साड़ी उपलब्ध कराने के प्रयास चल रहे हैं।

बजट की खास बातें...

1. वस्तु एवं सेवा कर विभाग का पुनर्गठन झ कर प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना
2. कार्यक्रम व्यय के लिए वित्त विभाग को 208 करोड़ रुपये का परिव्यय
3. श्रीनगर में महाराष्ट्र भवन और श्री राम जन्मभूमि अयोध्या झ 77 करोड़ रुपये का प्रावधान
4. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सतत पर्यटन नीति
5. लोनावाला, जिला पुणे में विश्व स्तरीय स्काईवॉक परियोजना– लागत 333 करोड़ 56 लाख
6. 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक औंधा नागनाथ जिला हिंगोली, साढ़े तीन शक्तिपीठों में से एक श्रीक्षेत्र महुरगढ़ जिला नांदेड़, एकवीरादेवी मंदिर जिला पुणे तीर्थ विकास प्राधिकरण की स्थापना

महाराष्ट्र को एक अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य

महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को एक अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखते हुए वित्तमंत्री अजीत पवार ने राज्य का अंतरिम बजट पेश किया। विधानसभा में पवार द्वारा पेश अंतरिम बजट में योजना विभाग के लिए 9 हजार 193 करोड़ रुपये, रोजगार गारंटी योजना के लिए 2 हजार 205 करोड़ रुपये और मराठी विभाग के लिए 71 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी गई है। जिला वार्षिक योजना के तहत 18 हजार 165 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य की वार्षिक योजना 1 लाख 92 हजार करोड़ रुपये है। अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 15 हजार 893 करोड़ रुपये और जनजातीय विकास उपयोजना के लिए 15 हजार 360 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये हैं।

किसानों को दिन में बिजली दी जाएगी

महाराष्ट्र बजट में कृषि विभाग को 3,650 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जबकि पशुपालन विभाग को 550 करोड़ रुपये दिए गए। महाराष्ट्र बजट में बकरी-भेड़ वराह योजना के तहत 129 प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित किए गए हैं। इसके लिए अगले तीन वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। इसके अलावा, किसानों को दिन में बिजली दी जाएगी। विदर्भ में सिंचाई के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 1 लाख महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर और 37 हजार आंगनबाड़ियों के लिए सोलर एनर्जी का प्रावधान किया गया है। रूफ टॉप सोलर योजना के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी।

वसोर्वा बांद्रा सी ब्रिज से पालघर तक सात हजार किलोमीटर सड़क विकास की योजना है। भारत की पहली मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है, जबकि सोलापुर, तुलजापुर और धाराशिव में रेलवे लाइनों के लिए काम जारी है।

माहिम दरगाह ट्रस्ट द्वारा शेख एसरेफ एफेंदी (जर्मनी) के साथ इंटरफेथ संवाद

माहिम : पीर मखदूम साहेब चैरिटेबल ट्रस्ट और माहिम सोशल वर्कर नाइट हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज ऑफ कॉमर्स का आयोजन शेख एसरेफ एफेंदी (जर्मनी) के साथ इंटरफेथ संवाद सभी जाति के धर्म गुरु विद्वान के साथ किया गया, मकसद भाईचारा और एकता का संदेश देना था ।

रामदास अठावले का राज ठाकरे पर बड़ा बयान

'NDA से हाथ मिलाने के बजाय...'

मुंबई : केंद्रीय मंत्री और आरपीआई (ए) के अध्यक्ष रामदास अठावले ने सोमवार को कहा कि राज ठाकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए. अठावले ने यहां संवाददाताओं से कहा कि राज ठाकरे की पार्टी यदि बीजेपी नीत गठबंधन से हाथ मिलाने के बजाय अकेले चुनाव लड़ती है तो उसे अधिक फायदा हो सकता है. मनसे के आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी, शिवसेना और राकांपा के 'महायुति' गठबंधन में शामिल होने की अटकलें चल रही हैं.

इस नेता से मुलाकात के बाद गर्म हुआ था चचाओं का बाजार

मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने हाल में राज ठाकरे से उनके मुंबई स्थित आवास पर मुलाकात की थी. सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री अठावले ने कहा, ''मनसे को NDA में शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है. मैं NDA के साथ हूं और मनसे को गठबंधन में नहीं लेना चाहिए.'' उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आरपीआई (ए) आगामी लोकसभा चुनाव में सोलापुर और शिरडी लोकसभा सीटों पर दावा करेगी और विधानसभा चुनाव के लिए भी कम से कम 8 से 10 सीटों पर दावा करेगी.

क्या बोले रामदास अठावले?

अठावले ने कहा, ''महायुति के नेताओं को लोकसभा चुनाव के लिए सीटों को अंतिम रूप देते समय आरपीआई को विश्वास में लेना चाहिए.'' उन्होंने कहा कि वह वरिष्ठ राजनेता शरद पवार की वजह से राजनीति में शामिल हुए थे. अठावले ने कहा, ''पवार ने मुझे कैबिनेट में शामिल किया था. पहले मैं उनके साथ था, लेकिन मैं बाद में एक गठबंधन में शामिल हो गया. पवार को बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का फैसला लेना चाहिए था.'' उन्होंने मराठा आरक्षण आंदोलन कार्यकर्ता मनोज जरांगे को बोलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी.

वर्ली में भी शुरू हुआ सी फूड प्लाजा, कोली महिलाओं को मनपा दे रही रोजगार

माहिम : माहिम कोलीवाडा में महिलाओं को रोजगार देने के लिए शुरू किया गया सी फूड प्लाजा का सफल प्रयोग के बाद अब वरली कोलीवाडा में भी सी फूड प्लाजा शुरू किया गया जिसका उद्घाटन राज्य के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने किया। इस दौरान बिजली से चलने वाले फूड ट्रक की भी शुरूआत की गई। मुंबई में मूल लोग में कोली समाज यहा का मूल निवासी माना जाता है। अभी तक कोलीवाडा का विकास नहीं होने पर राज्य सरकार ने मुंबई मनपा से मिलकर इन स्थानों का पर्यटन स्थल के रूप में विकास करने और कोली समाज की महिलाओं को सी फूड के जरिए रोजगार उपलब्ध कराना शुरू किया है। माहिम चौपाटी पर शुरू किए गए सी फूड प्लाजा का अच्छा परिणाम मिलने के मनपा ने वर्ली कोलीवाडा में भी इस तरह का प्रयोग शुरू किया है।

संपादकीय / लेख

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

खसरे का प्रकोप

अमरीका, यूरोप, ब्रिटेन के बाद भारत में खसरा फैल रहा है। हालांकि यह कोरोना महामारी सरीखा जानलेवा संक्रमण नहीं है, लेकिन त्वचा से जुड़ा खतरनाक संक्रमण जरूर है। इसे घरेलू स्तर पर 'माता', 'चेचक', 'शीतला माता' कहा जाता है और घरेलू, देशी टोटकों से ही इसका इलाज करने की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन समय पर खसरे का यथोचित मेडिकल इलाज न किया जाए, तो यह गंभीर जटिलताओं, आजीवन विकलांगता और अंततः मौत का कारण भी बन सकता है। यह फेफड़ों और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है। निमोनिया, मेनिनजाइटिस, अंधापन और दौरे का कारण भी बन सकता है। भारत में खसरे के संक्रमण का फैलाव चिंताजनक है, क्योंकि देश में औसतन हर साल करीब 10 लाख लोग खसरे का शिकार होते हैं। हालांकि औसतन मौत का कोई निश्चित डाटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतने व्यापक स्तर पर लोग संक्रमित होते हैं, तो जाहिर है कि मौत का संभावित आंकड़ा भी उसी के अनुपात में ही होगा! खसरे के कुछ लक्षण कोरोना वायरस सरीखे हैं। यह संक्रमण भी किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से, मुंह की लार से, हाथ मिलाने या गले लगाने से, गर्भावस्था या प्रसव अथवा देखभाल के दौरान मां से बच्चे को हो सकता है।

खांसने या छींकने का वायरस हवा में और सतहों पर रह सकता है। यदि कमरे में खसरा पीड़ित है और वह वहां से चला गया है, तो आप एक घंटे बाद ही वहां जाएं। यह सावधानी न बरतने पर खसरे से संक्रमित होने का खतरा 90 फीसदी है। संक्रमित के मुंह या नाक से बहते द्रव्य के सीधे या हवा के जरिए संपर्क में आने से भी संक्रमण हो सकता है। ये विभिन्न डॉक्टरों के शोधों और प्रयोगों के ही निष्कर्ष हैं। त्वचा पर लाल दाने या चकत्ते निकल आएं और उनमें तेज खुजली और जलन हो, तो ये खसरे के शुरूआती लक्षण हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत, अमरीका और यूरोप में खसरे के फैलते संक्रमण पर चिंता जताई है और चेतावनी भी जारी की है। खसरा लाइलाज वायरस नहीं है। बाजार में इसके टीके उपलब्ध हैं। टीकाकरण खसरा रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। खसरा और रूबेला का टीका आमतौर पर दो खुराक में दिया जाता है। पहली खुराक बच्चे को 12-15 माह की उम्र में ही देनी चाहिए और दूसरी खुराक 4-6 साल की उम्र में दी जाती है। हालांकि भारत में खसरा टीकाकरण की सुविधाएं मौजूद हैं, फिर भी 2022 में करीब 11 लाख बच्चे भारत में खसरे के टीके की पहली खुराक लेने से ही चूक गए। यह आंकड़ा विश्व स्वास्थ्य संगठन का है। नतीजतन भारत उन 10 देशों की जमात में आ गया, जहां महामारी के बाद भी खसरे के टीकाकरण में सबसे ज्यादा कमी आई है। वैज्ञानिकों और चिकित्सकों का मानना है कि टीका खसरे को रोकने में काफी असरदार है। किसी स्कूल या समुदाय में टीकाकरण दर 93 फीसदी या उससे अधिक है, तो उसकी सामूहिक प्रतिरक्षा काम कर सकती है। भारत सरकार विभिन्न टीकाकरण के अभियान चलाती रही है और लगभग सभी टीके मुफ्त ही लगाए जाते हैं, फिर भी 11 लाख बच्चों से जुड़ी कोताही की जाएगी, तो यही संक्रमण एक दिन 'महामारी' भी साबित हो सकता है। ब्रिटेन में चिकित्सक मानते हैं कि खसरे के मद्देनजर स्वास्थ्य की अनदेखी हुई है। नियमों की अवहेलना की गई है और अब काफी खराब हालात हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, 2021 में दुनिया भर में खसरे से करीब 1,28,000 मौतें हुई थीं। यह अनुमानित आंकड़ा है। अब तीन साल बाद मौतों का आंकड़ा अधिक भी हो सकता है। मरने वाले लोगों की औसतन उम्र 5 साल से कम बताई जा रही है। ये कोई सामान्य आंकड़े नहीं हैं। खतरनाक तथ्य है कि खसरे के मामले 30 गुना बढ़े हैं, लेकिन टीकाकरण की औसत दर गिरती रही है। चूंकि कोरोना वैश्विक महामारी के बाद अब लोग खुल कर विदेश यात्राएं कर रहे हैं, लिहाजा खसरे का संक्रमण भी एक-दूसरे देश में फैल रहा है।

+91 99877 75650
editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalrokthok
#faisalrokthok

महाराष्ट्र के स्पीकर ने फडणवीस के खिलाफ जारांगे-पाटिल के आरोपों की SIT जांच के निर्देश दिए

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मंगलवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मराठा कोटा एक्टिविस्ट मनोज जारांगे-पाटिल के आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दें. जारांगे-पाटिल ने इस महीने की शुरूआत में एक बयान में आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता फडणवीस ''सलाइन के जरिए जहर देकर उन्हें खत्म करने की साजिश रच रहे थे''. भाजपा विधायक आशीष शेलार द्वारा सदन में इसकी मांग करने के बाद नार्वेकर ने जांच की मांग की.

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं ने आरोप लगाया है कि शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए मनोज जारांगे-पाटिल के मराठा आंदोलन को ''उनके राजनीतिक सहयोगियों द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है'' और उन्होंने अभियान के दौरान उत्तेजक बयान दिए.

बांद्रा पश्चिम के बीजेपी विधायक शेलार ने कहा, ''आंदोलन के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? आंदोलन के बेकाबू होने का जिम्मेदार कौन? पथराव के लिए पत्थर कौन लाया? वे किस नेता से मिलते हैं? वे कहां रहते हैं? वे किस राजनीतिक दल का प्रचार कर रहे थे? हर चीज की जांच करने की जरूरत है और एक एसआईटी गठित करने की जरूरत है.''

जारांगे-पाटिल के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए फडणवीस ने सदन के पटल पर कहा: ''मुझे मनोज जारांगे-पाटिल के बारे में बोलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर मुझे अभद्र भाषा में गाली देना, यह सब क्या है? बीड़ हिंसा की भी जांच होनी चाहिए. संभाजीनगर और नवी मुंबई में वॉर रूम की शुरूआत किसने की? इन सब की जांच की जाएगी.

बांध टूटने से मलबे में दबे 4 बच्चे... 2 की मौत!

रायगढ़ : महाराष्ट्र के रायगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल रायगढ़ जिले के उरण तालुका के धुतुम गांव में एक बांध के टूट जाने के कारण 2 बच्चों की मौत हो गई है। सोमवार को पुलिस ने इस बाबत जानकारी साझा की। पुलिस ने कहा कि संरचना के ध्वस्त होने के बाद 4 बच्चे फंस गए थे। वहीं मलबे में दबे होने के कारण 2 बच्चों की मौत हो गई। आगे और जानकारी साझा करते हुए पुलिस अधिकारी ने

कहा कि मलबे में दबे 2 अन्य बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज गया।

उरान तालुका के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सतीश निकम ने बताया धुतुम गांव में उरान के करीब बांध के टूट जाने के कारण 4 बच्चे उसमें फंस गए थे। दो बच्चों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इस दौरान दो अन्य बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की मौत मलबे में दब जाने के कारण हुई है। इस घटना के बाद प्रशासन के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और आगे की जांच की जा रही है।

साढ़े चार लाख रूपए का आभूषण चोरी

भिवंडी : भिवंडी शहर व आसपास इलाकों में दररोज चोरी की घटनाएं घटित हो रही है। पुलिस चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। चोरों को लेकर नागरिकों में भय व्याप्त है। इसी क्रम में एक बार फिर अज्ञात चोर ने एक मकान में प्रवेश कर 4 लाख 59 हजार 700 रुपए कीमत के आभूषण को चोरी कर लेने की घटना घटित हुई है। पुलिस ने मकान मालिक की शिकायत पर अज्ञात चोर के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक काल्हेर के रेती बंदर रोड़ पर स्थित रिद्धी सिद्धी पैलेस के मकान नंबर 101 में अज्ञात चोर ने कल दोपहर में दरवाजे का लॉक तोड़कर प्रवेश किया और बेडरूम के कपाट में रखे 4,59,700 रुपए कीमत के सोने व चांदी का आभूषण चोरी कर लिया।

नागपुर जिले में पैसे के विवाद में एक व्यक्ति ने पत्नी की कर दी हत्या

नागपुर : नागपुर जिले में एक गांव में पैसे के मामले पर बहस के बाद सोमवार तड़के एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और बाद में आत्महत्या का प्रयास किया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना नागपुर शहर से लगभग 30 किमी दूर बिद गणेशपुर गांव में हुई। अधिकारी ने कहा कि रंजीत नत्थू चौधरी (48) नाम के व्यक्ति ने कथित तौर पर दंपति के बीच पैसे के मामले पर तीखी बहस के कुछ घंटों बाद देर रात करीब 2 बजे अपनी 45 वर्षीय पत्नी की नींद में गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद चौधरी ने अपना गला काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। फिलहाल, गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।

मछुआरों के बच्चों का बंदरगाह निर्माण के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन...

पालघर : विस्तार बंदरगाह के निर्माण के लिए केंद्रीय पर्यावरण विभाग द्वारा दिए गए अवैध अनापत्ति प्रमाण पत्र के खिलाफ पालघर जिले में भूमिपुत्रों का सरकार विरोधी आक्रोश हर जगह देखा गया है। हाल ही में बंदरगाह विरोधी संगठनों ने मुंबई- अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग को चार घंटे तक अवरुद्ध कर चक्का जाम कर दिया था. जहां कई चैनलों के माध्यम से यह खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंदरगाह का ऑनलाइन उद्घाटन करने वाले हैं, वहीं महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड ने घोषणा की है कि वह मुरबे खाड़ी में एक और नया बंदरगाह बनाएगा और डर है कि ''दर्टी कार्गो'' लिए हानिकारक सामान इस बंदरगाह में उतारे जाएंगे। यह हर जगह आना शुरू हो गया हैराज्य सरकार की इन सभी अवैध नीतियों के खिलाफ धाकटी दहानू गांव के मछुआरों के छोटे- छोटे बच्चों ने महागठबंधन सरकार की शव यात्रा निकाली और मुख्यमंत्री और दोनों मुख्यमंत्रियों का पुतला फूंका और इसे रद्द करने की मांग की। पगारन का बंदरगाह और मुरबे का बंदरगाह हमेशा के लिए सरकार के अंतिम संस्कार की योजना बनाने के लिए धाकटी दहानु के सक्रिय मछुआरों द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था।

गाड़ियों पर कार्रवाई कर रहे ट्रैफिक कर्मी पर हमला

मुंबई : डीएन नगर पुलिस थाने की हद में कार्यरत ट्रैफिक पुलिसकर्मी से हाथापाई करने के मामले में मले में वसोर्वा पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। ट्रैफिक कॉन्स्टेबल वसोर्वा इलाके में मौजूद एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी गाड़ियों पर कंट्रोल की जानकारी के बाद कार्रवाई करने पहुंचे थे। तभी अचानक तीन लोग आए और एक कॉन्स्टेबल को मारकर भागने लगे। जानकारी के मुताबिक मामले में अशोक अरेली और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 34, 353 और 504 के तहत

एफआईआर दर्ज किया है। पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल में आई शिकायत के बाद अजय गोविंद कार्लेकर (56) और एएसआई संदेश ढकले वसोर्वा इलाके में मौजूद रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी गाड़ियों पर कार्रवाई करने पहुंचे।

परेशानी मोल ली... अंजाम भुगतेंगे, केस दर्ज होने पर भड़के मनोज जरांगे ने दी महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी !

मुंबईः महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीड जिले में मनोज जरांगे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मनोज जरांगे पाटील पर बिना अनुमति के समर्थकों के विरोध प्रदर्शन करने और दो अलग-अलग स्थानों पर सड़क बंद करने का आरोप है। पुलिस ने उनके खिलाफ दो मामले दर्ज किए गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि दोनों घटनाओं में जरांगे घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके समर्थक उनकी अपील पर सड़कों पर उतर आए थे, इसलिए उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए। लगभग 80 लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है। शनिवार को शिरूर गांव के जतनंदूर फाटा और बीड जिले के पटोदा में बीड-अहमद नगर रोड पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए थे और सड़कें अवरुद्ध कर दी गईं। मराठवाड़ा के 1041 लोगों और बीड जिले के 425 लोगों के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में मामला दर्ज किया गया है। इधर मनोज जरांगे ने इस मामले पर सरकार को चेतावनी दी है।

मनोज जरांगे ने दी चेतावनी

उधर, केस दर्ज किए जाने पर मनोज जरांगे ने एकनाथ शिंदे सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर वे मुझ पर मुकदमा चलाना चाहते हैं, तो मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऐसा करके वे और परेशानी मोल लेंगे। लोग नाराज होंगे और सीएम और गृह मंत्री को इसके परिणाम भुगतने होंगे। अब यह उनका फैसला है।

लगातार आंदोलन और भूख हड़ताल के कारण मनोज जरांगे का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। उनके स्वास्थ्य को कुछ राहत मिलनी चाहिए। इसलिए उन्हें आराम करना चाहिए। सरकार किसी से भी चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार हैं। उन्हें आरक्षण के बारे में सरकार से जो कहना है कहें, सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। लेकिन बार-बार भूमिका बदलने और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने से मनोज जरांगे पाटील में मराठा समाज का भरोसा कम हो रहा है। मंत्री शंभूराज देसाई मनोज जरांगे पर बारबार अपनी भूमिका बदलने का आरोप भी लगाया। शंभूराज देसाई ने मनोज जरांगे के समूचे आंदोलन की हकीकत बयान की। देसाई ने कहा कि मराठवाड़ा के नौ जिलों में सबसे पहले उन लोगों के उत्तराधिकारियों के कुनबी पंजीकरण की शुरूआत हुई जिनके पूर्वजों के पास कुनबी रिकॉर्ड थे। उस समय जरांगे पाटील ने जो कहा था वह यह था कि रक्त संबंधियों को कुनबी प्रमाणपत्र दें। सरकार ने उनके मामले में निर्णय लिया। लेकिन बाद में उन्होंने इसे पूरे महाराष्ट्र में लागू करने की मांग कर दी। इस बारे में कैबिनेट में फिर चर्चा हुई। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं फिर से काम पर लगा दीं।

जब मराठा समुदाय को स्वतंत्र आरक्षण देने की बात आई तो एक स्वतंत्र आयोग तैयार किया गया। शिंदे समिति नियुक्त की गई। शिंदे समिती की रिपोर्ट आने के बाद हमने पूरे महाराष्ट्र में एक लाख से ज्यादा कार्यकताओं को इसी काम में लगाया। एक विस्तृत सर्वेक्षण के बाद हमने डेटा तैयार किया। इसके बाद कानून के कसौटी पर खरा उतरने वाला आरक्षण मराठा समाज को दिया। लेकिन इसके बाद भी जरांगे पाटील की भूमिका की भूमिका बदलनी शुरू हो गई। उन्होंने कभी मुख्यमंत्री शिंदे पर आरोप लगाया, कभी गृहमंत्री फडणवीस पर आरोप लगाया। इस बार उन्होंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर जो आरोप लगाए और जिस तरह की भाषा का उन्होंने उपयोग किया। उससे मराठा समुदाय में भी नाराजगी है। ऐसा लगता है कि पीछे से कोई उन्हें बता रहा है और वो बातें कर रहे हैं।

झुग्गी बस्ती में आग लगने से 35 झोपड़ियां जली... कोई हताहत नहीं

ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले में सोमवार सुबह एक झुग्गी बस्ती में आग लगने के कारण कम से कम 35 झोपड़ियां खाक हो गईं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। नागरिक आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तडवी ने कहा कि सुबह 10 बजे के आसपास अंबरनाथ शहर के सर्कस ग्राउंड इलाके में हुई घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। उन्होंने बताया कि आग से करीब 35 झोपड़ियां जल गईं, हालांकि लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। अधिकारी ने बताया कि आग पर एक घंटे में काबू पाया जा सका। उन्होंने कहा कि आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल सका है।

दो व्यक्तियों ने की आत्महत्या, केस दर्ज

नालासोपारा : अलग-अलग पुलिस स्टेशन क्षेत्र में दो लोगों द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की घटना सामने आई है। इस विषय में पेल्हार व वसई पुलिस स्टेशन ने दोनों आत्महत्या मामले में सीआरपीसी कलम 174 के तहत केस दर्ज कर आगे की तहकीकात में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार, स्वप्निल कालूराम रायत (28) निवासी- नवापाड़ा वसई में रहता था। बताया गया है कि, स्वप्निल किसी अज्ञात कारण को लेकर डिप्रेशन में आकर रूम के छत पर लगे लोहे की पाइप में साड़ी की सहायता से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। इसी क्रम में बालाजी शिवाजी नेताबाजे (34), निवासी-नवजीवन वसई पूर्व में रहता था।

बसपा ने ईवीएम के खिलाफ खोला मोर्चा

भिवंडी : तालुका के बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा ईवीएम मशीन के खिलाफ भिवंडी से जिला अधिकारी कार्यालय ठाणे तक पैदल मार्च निकाला गया। बसपा समर्थकों ने भाजपा द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोटिंग पर सवाल उठाया और भारत में ईवीएम को बंद करने और पुरानी प्रणाली बेल्ट पेपर से चुनाव करवाए जाने की मांग की। बसपा पदाधिकारियों ने जिला अधिकारी सहित राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम का ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा।

पालघर जिले में बढ़ता टी.बी. का प्रकोप... सालभर के भीतर टी.बी. से 54 लोगों की मौत !

रोगियों की बढ़ती संख्या से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ी

पालघरः पालघर जिला टी.बी से ग्रस्त है और इस बीमारी ने एक वर्ष में 54 लोगों की जान ले ली है। जिले में 2949 मरीज अभी भी टीबी से जूझ रहे हैं। विशेष रूप से भारत संकल्प यात्रा के दौरान की गई स्क्रीनिंग के दौरान 1974 संदिग्ध मामले पाए गए, पालघर और दहानू तालुका में टी.बी. रोगियों की संख्या बहुत अधिक है। चिकित्सीय जांच के दौरान जिले के 77 हजार मरीजों में से करीब 34 हजार मरीजों की क्षय रोग की जांच की गयई। इनमें से प्रारंभिक जांच में 1974 मरीजों की व्यापक जांच की जा चुकी है और 140 मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया है. जिले में पूर्व में दवा प्रतिरोधी क्षयरोग के 49 तथा दवा के प्रति संवेदनशील रोगियों की संख्या 2900 होने से काफी वृद्धि होने की संभावना है। टी.बी. रोगियों की बढ़ती संख्या स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा रही है। यह पता चला है कि टी.बी के रोगियों की मृत्यु का कारण यह है कि वे दवा लेने में अनिच्छुक हैं, लेकिन मौत के आंकड़ों से पता चलता है कि स्वास्थ्य विभाग इस ओर ध्यान देने में नाकाम हो रहा है। जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था अब भी पटरी पर नहीं है। सरकार की निक्षय पोषण योजना से टी.बी. रोगियों को 500 और उससे अधिक 509 रुपए प्रति माह सब्सिडी दी जाती है ताकि टी.बी रोगियों को स्वस्थ आहार मिल सके। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि यह योजना सभी मरीजों तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि टी.बी रोग के लिए सरकारी अस्पतालों में एक्स-रे की सुविधा उपलब्ध करायी गई है, लेकिन कुछ जगहों पर एक्स-रे मशीनें बंद हैं, कुछ स्थानों पर एक्स-रे तकनीशियन उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीजों को निजी केंद्रों पर जाना पड़ता है। इसलिए वे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। हालांकि कई स्थानों पर टी.बी. जांच केंद्र उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन समय लेने वाली प्रक्रिया के कारण मरीज इन केंद्रों पर नहीं जाते हैं। हालांकि सरकार के पास टी.बी. उन्मूलन के लिए पर्याप्त धनराशि है, फिर भी प्रशासन इस बीमारी के लिए सामाजिक जिम्मेदारी और दानदाताओं की तलाश कर मदद क्यों ले रहा है, यह शोध का विषय बन गया है।

अवैध बैनर पोस्टर के मालिकों पर पालिका ने दर्ज कराया केस

पोस्टर लगाने के लिए पालिका से नहीं ली थी परमिशन

भिवंडी : भिवंडी महानगर पालिका क्षेत्र अंर्तगत अवैध रूप से बिजली के खंबे, दीवार व उड़ान पुलों के खंबो पर पोस्टर व बैनर लगा कर शहर में स्वच्छता फैला रहे कंपनियों, संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पालिका आयुक्त के सभी प्रभाग के प्रभारी सहायक आयुक्तों को निर्देश दिये है। तदुपरांत अवैध रूप से बैनर पोस्टर लगाने वालों संस्थानों के खिलाफ प्रभाग स्तर पर कार्रवाई सतत जाती है और स्थानीय पुलिस थानों में ऐसे संस्थानों के खिलाफ फौजदारी संहिता के तहत केस भी दर्ज कराऐ जा रहे है। इसी क्रम में प्रभाग समिति क्रमांक पांच के सहायक आयुक्त बालाराम जाधव ने छुट्टी के दिन शनिवार और रविवार को अपने क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दरमियान मंडई के बीजेपी दवाखाना के सामने टीडीसी बैंक के पास पालिका की बिजली के खंबे पर सेंटर पब्लिक स्कूल द्वारा बैनर पोस्टर लगाया हुआ दिखाई पड़ा। स्कूल द्वारा बैनर पोस्टर लगाने के लिए पालिका से परमिशन अथवा अनुमति नहीं ली थी। जिसके कारण सहायक आयुक्त ने निजामपुरा पुलिस थाने में अयाज अहमद खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया है।

महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर एक जंगल से छह लाख की इनामी नक्सली कमला पडगा गोटा गिरफ्तार

मुंबईः महाराष्ट्र की गढ़चिरौली पुलिस ने सोमवार को 30 साल की एक इनामी महिला नक्सली को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार महिला नक्सली का नाम राजेश्वरी उर्फ कमला पडगा गोटा है जिस पर 6 लाख रुपये का इनाम घोषित है.

गढ़चिरौली पुलिस ने सक्रिय रूप से विभिन्न गतिविधियों में शामिल एक कट्टर महिला माओवादी को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया. जो सुरक्षा बलों के खिलाफ कई हिंसक घटनाएं में लिप्त थी. भामरागड में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने कहा कि गढ़चिरौली से गिरफ्तार महिला नक्सली कथित तौर पर सुरक्षा बलों पर हुए हमलों में शामिल थी और उस पर 6 लाख रुपये का इनाम था. पुलिस ने एक विज्ञप्ति में कहा कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले की मूल निवासी राजेश्वरी उर्फ कमला पडगा गोटा को रविवार को महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर एक जंगल से पकड़ा गया. विज्ञप्ति में कहा गया है कि गोटा अप्रैल 2023 में भामरागढ़ के केदमारा वन क्षेत्र में पुलिस और माओवादियों के बीच गोलीबारी, छत्तीसगढ़ के कचलाराम वन क्षेत्र में पुलिस दलों पर गोलीबारी और हिंसा की अन्य घटनाओं में कथित रूप से शामिल थी.

मुंबई के टाटा इंस्टिट्यूट ने खोजा इलाज... दूसरी बार कैंसर होने से रोकेगी टैबलेट

मुंबई: कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद भी कई मरीजों में यह वापस फैल जाता है। टाटा अस्पताल के डॉक्टरों ने अध्ययन कर इसका कारण खोजा है। टाटा अस्पताल के खारघर स्थित एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर (एक्ट्रेक) अस्पताल के डॉ. इंद्रनील मित्रा के नेतृत्व में शोध किया गया है। उन्होंने

बताया कि हमने चूहों पर शोध किया है। चूहों में मनुष्य के कैंसर सेल डाले गए। जिसके बाद उनमें ट्यूमर निर्माण हुआ। हमने रेडिएशन थेरेपी, कीमो थेरेपी और सर्जरी के जरिए उनका इलाज किया। इसके बाद कैंसर सेल्स नष्ट होकर उनके बहुत छोटे-छोटे टुकड़े हो गए। यह मरते हुए कैंसर सेल में से क्रोमेटिन कण (क्रोमोजोन के टुकड़े) रक्त वाहिनी के जरिए शरीर के दूसरे हिस्से में पहुंच जाते हैं। ये शरीर में मौजूद अच्छे सेल्स में मिल जाते हैं और उन्हें भी कैंसर सेल में तब्दील कर देते हैं। इस शोध से यह स्पष्ट हो गया है कि कैंसर सेल नष्ट होने बावजूद वापस आ जाते हैं। समस्या का हल खोजने के लिए डॉक्टरों ने चूहों को रेसवेरेट्रॉल और कॉपर (तांबा) के संयुक्त प्रो-ऑक्सिडेंट टैबलेट दी। यह टैबलेट क्रोमोजोन को बेअसर करने में असरदार रही। करीब एक दशक से टाटा के डॉक्टर्स इस पर शोध कर रहे हैं।

'कैंसर ट्रीटमेंट को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी'

टाटा मेमोरियल सेंटर के पूर्व निदेशक डॉ. राजेंद्र बडवे ने बताया कि कैंसर के इलाज को बेहतर बनाने की दिशा में अधिक शोध की जरूरत है। डॉ. मित्रा के शोध से दुनियाभर में कैंसर ट्रीटमेंट को और भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। टाटा मेमोरियल सेंटर के उपनिदेशक सेंटर फॉर कैंसर एपिडीमिलॉजी डॉ. पंकज चतुर्वेदी ने बताया कि समस्या की जड़ का पता लगाने के साथ-साथ उसका निवारण भी उतना ही जरूरी है। कॉपर- रेसवेरेट्रॉल के एक घरेलू नुस्खा है। कैंसर के इलाज को बेहतर बनाने और इलाज के दौरान होने वाले दुष्परिणामों को कम करने में भी मददगार साबित होता है। रेसवेरेट्रॉल अंगूर, बेरीज के छिलके सहित अन्य पदार्थों से मिलता है। कई खाद्य पदार्थों से भी कॉपर मिलता है।

साइड इफेक्ट को कम करता है

- टाटा के बोन मैरो ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉ. नवीन खत्री के अनुसार इलाज के दौरान मरीज के मुंह में छाले पड़ जाते हैं, कॉपर- रेसवेरेट्रॉल के सेवन से इस तकलीफ से काफी राहत मिलती है।
- मुंह के कैंसर की कोशिकाओं की आक्रामकता को कॉपर- रेसवेरेट्रॉल का टैबलेट देने के बाद कैंसर सेल की तीव्रता कम हो गई।
- पेट से संबंधित कैंसर मरीजों के इलाज के दौरान हाथ और पांव की स्किन छूटने के साइड इफेक्ट को भी कम करने में इससे मदद मिलती है।
- ब्रेन ट्यूमर के मरीजों में भी कॉपर- रेसवेरेट्रॉल के सेवन से बेहतर परिणाम मिले हैं।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाई फटकार

आरक्षण को लेकर जारी प्रदर्शन के बीच राज्य सरकार मूकदर्शक नहीं हो सकती...

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि मराठा आरक्षण को लेकर जारी प्रदर्शन के बीच राज्य सरकार मूकदर्शक नहीं हो सकती है। सरकार के पास कानून-व्यवस्था को कायम रखने के लिए पर्याप्त अधिकार हैं। जस्टिस अजय गड़करी और जस्टिस श्याम चंडक की बेंच ने कहा कि आंदोलन से पैदा हुई स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार को अदालत के आदेश की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट महाराष्ट्र में चल रहे मराठा आंदोलन को लेकर हो रहे प्रदर्शन, सड़क जाम और लोगों को हो रही परेशानियों पर बात कर रही थी।

हालात पर काबू के लिए अदालत के आदेश की जरूरत नहीं

हाई कोर्ट में जरांगे पाटील के आंदोलन के खिलाफ एक्टिविस्ट गुणरत्न सदावर्ते की याचिका पर सुनवाई चल रही है। पिछले सप्ताह पाटील ने अपने वकील वी एम थोरात के माध्यम से कोर्ट को अश्वस्त किया था कि वे शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करेंगे। सोमवार को सुनवाई के दौरान सदावर्ते ने बेंच के सामने कहा कि राज्य के कई इलाकों में आंदोलन हिंसक हो गया है। कोर्ट ने 5 मार्च को याचिका पर अगली सुनवाई रखी है।

इससे पहले राज्य के महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ ने कहा कि हिंसक घटनाओं के चलते राज्य भर में 267 मामले दर्ज किए गए हैं। इस पर बेंच ने कहा कि सरकार के पास स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं। वह आंदोलन से जुड़ी घेरेबंदी को हटा सकती है। यदि पाटील खुद के शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने के वादे पर कायम नहीं रहते है, तो हालात को काबू में रखना सरकार का दायित्व है, ताकि आम लोगों को आंदोलन के चलते परेशानी न हो।

पाटील का पक्ष रख रहे वकील ने कहा कि इस तरह के राजनीतिक मामलों को कोर्ट में नहीं लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिले आश्वासन के बाद 26 जनवरी को अपने आंदोलन को खत्म करने की बात कही थी, लेकिन अब तक मांग पूरी न होने के चलते आंदोलन का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि पाटील का आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।

सड़क चौड़ा करने में बाधा बने रहे 168 झोपड़े तोड़े गए

मुंबई : गोरेगांव पूर्व और कांदिवली पूर्व में लगभग 2.1 किमी दूरी में सड़क को चौड़ा करने का काम अब आसान हो गया। मनपा पी नॉर्थ वार्ड की ओर से की गई कार्रवाई में सोमवार को 168 झोपड़ा को निष्कासित किया गया। मनपा ने इस कार्रवाई के लिए बड़ी संख्या में मनपा कर्मियों और पुलिस का बंदोबस्त करना पड़ा था। मनपा ने तोड़क कार्रवाई करने के लिए जेसीबी का उपयोग किया गया। बता दें कि गोरेगांव पूर्व और कांदिवली पूर्व में सड़क को चौड़ा करने में 168 स्ट्रक्चर बाधा बन रहे थे।

मनपा पी नॉर्थ वार्ड की ओर से सोमवार को सड़क की बाधा बनने स्ट्रक्चर को तोड़ा गया। मनपा पी नार्थ के सहायक आयुक्त किरण दिघावकर ने जानकारी दी कि कुल 168 स्ट्रक्चर में 107 स्ट्रक्चर पात्र थे जिसमे 85 घर और 22 दुकानें है जिन्हे मनपा ने दूसरे स्थान पर घर और दुकानें उपलब्ध कराया। दिघावकर ने बताया की बकाया लोगों की पात्रता निश्चित करने का काम अभी जारी है लोगों से उनके कागजात मंगाए गए है। मनपा अधिकारी ने बताया कि सड़क को चौड़ा करने से नौ मीटर की सड़क अब 36 मीटर चौड़ा होगी। जीससे इस परिसर में होने वाली ट्रैफिक की समस्या दूर होगी। जिसकी लंबाई गोरेगांव पूर्व से लोखंडवाला कांदिवली पूर्व तक 2.1 किमी है।

नागपुर में पूर्व प्रेस फोटोग्राफर की हत्या

नागपुर : 54 वर्षीय फोटो जर्नलिस्ट विनय पूनेकर की हत्या के मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को बताया कि पूनेकर (54) की शनिवार को राज नगर स्थित उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी की पहचान साक्षी ग्रोवर (35) के रूप में हुई है। वहीं, मुख्य आरोपी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला हेमंत शुक्ला (35) फरार है।

उरण में गिरा 35 साल पुराना पुल... दो लोगों की दर्दनाक मौत, दो घायल

मुंबईः महाराष्ट्र के उरण में सोमवार को एक क्रीक पर स्थित पुल के ढह जाने से दो लोगों की मौत हो गई. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि दादरपाड़ा और धुडुस गांवों को जोड़ने वाला यह पुल शाम साढ़े पांच बजे ढह गया, जिससे मजदूर राजेश लक्ष्मण वाघमारे और अविनाश सुरेश मुरकुटे की मौत हो गई, जबकि दो घायल हो गए. उरण पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने कहा, ''वे पास के एक ईंट भट्टे पर काम करते थे और मछली पकड़ने के लिए निकले थे. पैंतीस साल पुराने पुल के गिरने के कारण वे फंस गए. घायल हुए दो मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.''

47 महीने तक पत्नी को नहीं दिया मेंटीनेंस, कोर्ट ने 47 महीने की दी जेल...

मुंबईः पत्नी को 47 महीने तक मेंटेनेंस न देने के लिए 47 माह के लिए जेल भेजे गए पति को बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहत दी है। हाई कोर्ट ने आर्थर रोड जेल को पति को रिहा करने का निर्देश दिया है। मुंबई की मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने जनवरी 2024 में पति को 47 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी। मैजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ पति ने हाई कोर्ट में अपील की थी। जस्टिस शर्मिला देशमुख के सामने पति की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस देशमुख ने कहा कि मौजूदा मामले में दिया गया मैजिस्ट्रेट का आदेश सीआरपीसी की धारा 125(3) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। मैजिस्ट्रेट इस मामले में एक माह से अधिकतम 12 माह की सजा दे सकते थे। महिला ने गुजारे भत्ते की मांग को लेकर 2018 में मैजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी दायर की थी। मैजिस्ट्रेट ने अंतरिम गुजारे भत्ते के रूप में पति को 15 हजार रुपये प्रतिमाह पत्नी को, जबकि 10 हजार रुपये प्रतिमाह नाबालिग बेटी को देने का निर्देश दिया था। भरण-पोषण की रकम 11 लाख 50 हजार रुपये हो गई थी। पति ने इसमें से केवल 3 लाख 25 हजार रुपये का भुगतान किया था। इसे देखते हुए मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने पति को 47 माह के लिए जेल भेज दिया था। सुनवाई के दौरान पति का पक्ष रख रहे वकील ने कहा कि मैजिस्ट्रेट ने इस मामले में अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर आदेश दिया है। वहीं पत्नी का पक्ष रख रह रही वकील ने कहा कि मौजूदा मामले में नाबालिग बेटी का भी गुजारा भत्ता बाकी है। इसलिए मैजिस्ट्रेट का आदेश उचित है। इन दलीलों को सुनने के बाद मैजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया, लेकिन पत्नी को नए सिरे से मेंटेनेंस की रकम की वसूली के लिए अर्जी करने की छूट दी गई है।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : शॉप नंबर ४ , मदीना मेंशन, ८९ ए, कैडल रोड, अपोजिट बिल्लाबोंग स्कूल, माहिम पश्चिम, मुंबई ४०००१६ , महाराष्ट्र मोबाइल नं 998777 5650 व्हाट्सप्प नं 7977408589: Email-editor@rokthoklekhaninews.com